आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 29.12.2024
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए।
- राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र से उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष निधि की मांग की।
- देहरादून में कूड़ा उठान का काम कर रही कंपनियों पर मानकों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।
- **और....**राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

मन की बात –1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है और अगले वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान हर मायने में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि

नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए एक विशेष वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से वेबसाइट पर जाने का आग्रह किया। लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और अपना वीडियो वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट संविधान को कई अलग–अलग भाषाओं में पढ़ने और संविधान से संबंधित प्रश्न पूछने का अवसर भी प्रदान करती है।

मन की बात –2

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय एनिमेशन फिल्मों, नियमित फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की लोकप्रियता दर्शाती है कि भारत के रचनात्मक उद्योग में कितनी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह उद्योग न केवल देश की प्रगति में योगदान दे रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने फिल्म और मनोरंजन उद्योग को बधाई दी क्योंकि इसने 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री ने यह बताते हुए खुशी जाहिर की कि पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स समिट, अगले साल भारत में आयोजित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि वेव्स समिट के दौरान दुनिया भर के दिग्गज शामिल होंगे।

मुलाकात/वित्तीय सहायता अनुरोध

राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए एक पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, जलापूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और चारधाम यात्रा के लिए विशेष निधि की मांग की गई। राज्य के शहरी विकास मंत्री ने स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 264 करोड़ रुपये की मांग की, जिसमें देहरादून और अन्य प्रमुख शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाओं का विकास शामिल है। इसके अलावा, राज्य के जलापूर्ति सुधार के लिए भी डॉक्टर अग्रवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से चार सौ नब्बे करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने चारधाम के मुख्य केंद्रों में प्रशासन और संचालन के लिए 200 करोड़ की विशेष मांग का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, वाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए की मांग भी की गई।

भारतीय ज्ञान परम्परा आधारित पाठ्यक्रम

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को समितियां गठित कर पाठ्यक्रम विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा

परिणामों को समय पर घोषित करने के लिए परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में द्वितीय कुलपति गोलमेज सम्मेलन–2024 का आयोजन किया गया।

इस सम्मेलन में राज्य के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने पर सहमति बनी। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति अपनी टीम के साथ देष के दो–दो प्रमुख विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे। उच्च षिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय समिति भी षिक्षा के अग्रणी देषों का षैक्षणिक दौरा करेगी। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि राज्य विश्वविद्यालयों में हर साल अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य में एनसीसी की सीटों में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृत सात हजार पांच सौ सीटों का जल्द आवंटन किया जाएगा।

सफाई व्यवस्था

देहरादून में कूड़ा उठान का काम कर रही कंपनियों पर मानकों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम कार्यालय में शहर में सफाई व्यवस्था की समीक्षा लेते हुए कहा कि कूड़ा उठान में कंपनियां सत्तर से अस्सी प्रतिशत तक ही काम कर पा रही हैं। उन्होंने कूड़ा उठान और पृथक्करण में मानकों का पालन न करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने कूड़ा उठान का काम कर रही दो कंपनियों को 15 दिन का समय दिया है और यदि इनके प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो नए टेंडर बुलाए जाएंगे। उन्होंने

कूड़ा उठान कार्यों के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था की शुरुआत के निर्देश भी दिए हैं।

वैली ब्रिज

चम्पावत जिले के अमोड़ी–छतकोट–न्याडी मोटर मार्ग के क्वैराला नदी पर पहला वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। लगभग 81 लाख रूपयों से निर्मित इस ब्रिज से अमोड़ी छतकोट न्याडी सड़क चम्पावत–टनकपुर राजमार्ग का विकल्प बनने के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र भी सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। ब्रिज निर्माण की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहन पलड़िया ने बताया कि इस पुल की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई छह मीटर है।

गौरतलब है कि बीते मानसून सीजन में टनकपुर चम्पावत एनएच 9 पर स्वाला के समीप लम्बे समय तक मार्ग बाधित रहने के कारण वैकल्पिक मार्ग निर्माण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने क्वैराला नदी पर पुल निर्माण करने व वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की घोषणा की थी।

डिजिटल मूल्यांकन

राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा परिणामों की समयबद्ध घोषणा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें किसी एक संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो भविष्य में इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा। देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में

आयोजित कुलपति गोलमेज सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि पांच साल पूरे कर चुके सरकारी महाविद्यालयों को स्थाई मान्यता दी जाएगी, जबकि निजी संस्थानों को तीन साल में स्थाई मान्यता दी जाएगी, बशर्ते वे सभी संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करें।

यातायात व्यवस्था

आगामी नव वर्ष और बर्फबारी के मौसम में मसूरी और चकराता जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, देहरादून पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने विशेष रूप से मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट्स और रूट डायवर्जन योजना का अवलोकन किया और सही दिशा–निर्देशों के लिए सड़क पर संकेतक और बैरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, गूगल मैप पर रूट अपडेट्स सुनिश्चित करने को भी कहा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नव वर्ष के मौके पर पर्यटकों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देने के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से तैयार है।

यू०पी०सी०एल

उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड– यू०पी०सी०एल शीतकाल में राज्य में बिजली आपूर्ति को निर्बाध रखने के लिए अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। क्षेत्रीय इकाइयों के तहत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें पल–पल की विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। शीतकालीन मौसम में प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।